

'मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता'—वेडेल फिलिप

भारतीय बस्ती

बस्ती 5 मई 2026 मंगलवार

सम्पादकीय

भगवा लहर

5 राज्यों को चुनावी नतीजों ने बड़े उलटफेर किए हैं। इससे देश के राजनीतिक नक्शे में कई बदलाव आए हैं। लेफ्ट अब राजनीतिक नक्शे से पूरी तरह बाहर हो गया है। वहीं भाजपा की अब 21 राज्यों में सरकार है या फिर वह उसका हिस्सा है। गंगोत्री से गंगासागर तक उसका पावर कॉरिडोर है। पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने देश के राजनीतिक नक्शे में कई बदलाव कर दिए हैं।

एक तरफ रिफॉर्ड बने हैं तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर ही बदल गई है। इसका असर आने वाले दिनों में राज्यसभा में दिखेगा तो वहीं राज्यों की सत्ता में भी भगवा प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। इस चुनाव ने केरल, बंगाल, तमिलनाडु और असम समेत देश के 5 राज्यों में रिफॉर्ड की बारिश कर दी है। सबसे बड़ा रिफॉर्ड तो यही है कि भाजपा को पहली बार बंगाल में सरकार बनाने का मौका मिला है। यह उसके लिए एक सपने के साकार होने जैसा है।

यही वह राज्य है, जहां के जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी रहने वाले थे। यही नहीं आरएसएस की विचारधारा के भी बंगाल काफ़ी करीब रहा है। संघ की विचारधारा में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले स्वामी विवेकानंद यहीं के थे। ऐसे में भाजपा का यहां पहली बार जीतना मायने रखता है। इस तरह ये चुनावी नतीजे कई रिफॉर्ड बना रहे हैं।

पहला रिफॉर्ड तो बंगाल की जीत ही है। यहां ममता बनर्जी की सरकार 15 साल की सत्ता के बाद गई है तो भाजपा को पहली बार चांस मिला है। चुनाव के दौरान मीडिया की हेडलाइंस इसी पर थीं कि ममता चौथी बार या पहली बार भाजपा सरकार का इनसे से दूसरी बात सही साबित हुई और पहली बार भाजपा सरकार बन रही है। इस जीत ने भाजपा के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। इसका असर राज्यसभा चुनावों में भी दिखेगा। यही नहीं कई तरह के मुद्दों के चलते भाजपा को बैकफुट में माना जा रहा था, लेकिन इस जीत से उसे फिर से नई ताकत मिलेगी।

कभी बंगाल और केरल वामपंथी किले माने जाते थे। खराब वक्त में भी लेफ्ट का यहां शासन बना रहा था। 2011 में ममता बनर्जी ने यहां जीत हासिल की थी और तब से अब तक लेफ्ट यहां से सत्ता से बाहर है। उसके बाद केरल ही एकमात्र राज्य था, जहां उसकी सरकार थी। अब केरल में कांग्रेस की लीडरशिप वाले यूडीएफ को जीत मिली है। इसके साथ ही लेफ्ट का भारत के राजनीतिक नक्शे से एरिजट हो चुका है।

भाषायी अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति करने वाली डीएमके को करारा झटका तमिलनाडु में लगा है। एमके स्टालिन की 10 साल पुरानी सरकार विदा हो गई है। इसके अलावा एक्वटर विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने अकेले ही 110 सीटों पर बढ़त बना रखी है। तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेताओं के नेता बनने का पुराना इतिहास रहा है। हालांकि स्टालिन खुद को काफ़ी मजबूत मान रहे थे। ऐसे में नौसिखाय कहे जा रहे विजय की बंपर जीत ने सारे समीकरण ही उलट-पलट दिए हैं। तमिलनाडु में जादुई आंकड़ा 117 का है। इस तरह वह अकेले दम पर भी सत्ता हासिल करने के करीब है।

अब भगवा लहर का बात की जाए तो यह 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है। यह भाजपा के लिए कामयाबी के नक्शे पर बढ़ते कदम जैसा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, असम, ओडिशा, पुडुचेरी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और आंध्र प्रदेश में फिलहाल भाजपा जीत लिए उसके नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है।

बंगाल की जीत ने पीएम मोदी के सपने को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि हमारा भविष्य में लक्ष्य होगा कि बंगाल और ओडिशा में जीत मिले। 2024 के आम चुनाव के साथ ही ओडिशा में भाजपा को जीत मिली थी। अब बंगाल का किला भी उसने फतह कर लिया है।

यूपी में अखिलेश को भी लग सकता है



—अजय कुमार—

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शासनवादी जीत का जो तुफान आया है, उसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। यहां की जनता, खासकर हिंदू समुदाय ने एकजुट होकर ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति को करारा जवाब दिया। राज्य में वर्षों से चली आ रही मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ हिंदुओं ने वोट की ताकत से विद्रोह कर दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से बीजेपी को हराने के लिये मुस्लिम वोटर तुष्टिकरण की सियासत करने वालों के पक्ष में लामबंद होते हैं, उसी तरह से अब हिन्दू वोटर बीजेपी के पक्ष में एकजुट होकर वोटिंग करने लगे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी इतिहास दोहराया जाएगा? यहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत को एगजुट हिंदू वोटर रोके देंगे? क्या अब जात-पात के नाम पर हिंदू बंगाल बंटेंगे नहीं? और क्या पश्चिम बंगाल को फतह करने वाले रणनीतिगार सुनील बंसल एक बार फिर उत्तर प्रदेश की चुनावी जग में कमान संभालकर भाजपा को विजयी



बनाएंगे, जैसे उन्होंने 2017 में किया था?

उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जटिल रही है। यहां सत्ता का खेल जातिगत समीकरणों पर टिका होता है। समाजवादी पार्टी ने लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने पर जोर दिया है। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए कई कदम उठाए। पंचायत चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट बांटना, उनके क्षेत्रों में विकास के नाम पर विशेष योजनाएं चलाना और हिंदू त्योहारों पर विवादग्रस्त बयान देकर तुष्टिकरण का राग अलापना, ये सब उनकी सियासत का हिस्सा बने। लेकिन पश्चिम बंगाल का उदाहरण सबके समने है। यहां ममता बनर्जी ने भी इसी फॉर्मूले पर दांव लगाया था। रामनवमी पर जुलूसों पर पाबंदी लगाना, हिंदू मंदिरों के आसपास दुकानों पर कार्रवाई और मुस्लिम

समुदाय को वोट के बदले लाम पहुंचाना, गुनसुनें के जगाने दिया। नतीजा सबके सामने है। भाजपा ने वहां हिंदू एकाता का झंडा बुलंद किया और भारी सफलता हासिल की। पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश के हिंदू वोटर भी अब यूनाइटेड होने की बात करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाएं अब धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक संदेश गुंज रहे हैं और जातिगत बंटवारे की पुरानी चाल अब काम नहीं आती। पश्चिम बंगाल की जीत में भाजपा के रणनीतिकार सुनील बंसल की भूमिका अहम रही। उन्होंने हिंदू एकाता पर जोर दिया। बंगाल के हर कोने में हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए सूक्ष्म रणनीति बनाई। गांग-गांग जाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, धार्मिक नेताओं से संकेंद सभाएं और मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ जन जागरण अभियान

चलाया। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सुनील बंसल ने यहीं जादू दिखाया था। तब भाजपा ने जातिगत समीकरण तोड़े। झाड़ग, ठाकुर, दलित, ओबीसी समी को एक मंच पर लाकर अखिलेश की सभा को पछखनी दी। यूपी आदिवाल्या के नेतृत्व में हिंदुत्व का मुद्दा उठा और विकास के वादों ने वादों को लुभाया। आज फिर वही हालात हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सुनील बंसल की भाषणी की चर्चा जागे पर है। क्या ये एक बार फिर कमान संभालेंगे? उनके पास अनुभव है, नेटवर्क है और हिंदू एकाता का मंत्र है। अगर भाजपा उन्हें जिम्मेदारी सौंपती है, तो अखिलेश की राह कठिन हो जाएगी।

दरअसल, उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण अब बदल चुके हैं। पहले हिंदू वोट जाति के आधार पर बंटते थे। जाटव दलित बसपा की ओर

ममता वाला झटका

यादव सपा की तरफ, ब्राह्मण और ठाकुर भाजपा के साथ। लेकिन जब हिंदू एकाता का दौर चल पड़ा है। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर यहां भी राम मंदिर निर्माण, काशी विध्वनयन कॉरिडोर और अयोध्या विकास ने हिंदुओं को जोड़ा है। सोशल मीडिया ने जागरूकता फैलाई है। हर छोटे-बड़े हिंदू नेता अब तुष्टिकरण के खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश की सभा अब सिर्फ मुस्लिम वोट पर निर्भर नहीं रह सकती। उनके पास मुस्लिम तुष्टिकरण के अलावा कुछ अन्य रास्ते खुले हैं। सबसे बड़ा रास्ता है युवाओं को लुभाना। सपा ने पहले भी लैपटॉप वितरण जैसी योजनाओं से युवा वोट हासिल किया था। अब वे बेरोजगारी, किसान कर्जमाफी और ग्रामीण विकास पर जोर दे सकते हैं। दूसरा रास्ता है गठबंधन की राजनीति। बसपा के साथ गुजरात गजबोज दौरेवाना या छोटी जितियां को सामाना। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण होगा हिंदू ओबीसी वोट को लड़ना। कुर्मी, मोंग, निगार जैसे समुदायों को साने में कभी मजबूत नहीं किया।

अगर अखिलेश इनके लिए लिए आश्रय या योजनारो घेषित करें, तो कुछ सफलता मिल सकती है। तीसरा रास्ता है विकास का। पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा अभियान और शहरीकरण जैसे मुद्दे पर सपा और कांग्रेस वाद देकर, तो शहरी हिंदू वोटर आकर्षित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लेकर महानगर तक हिंदू समाज में उत्साह है। धार्मिक उत्सवों में राजनीतिक बहस हो रही है।

लोग कह रहे हैं, अब जात-पात नहीं, हिंदू एकाता ही सौभाग्य। अखिलेश अगर नहीं चेंते, तो सपा का सफर सबसे बाजूदर मुस्लिम तुष्टिकरण छोड़ना होगा, वरना हिंदू एकाता सबको नेस्टानाबूट कर देगी। इस सबके बीच यह हकीकत है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हवा का रस बदल रहा है। पश्चिम बंगाल ने साबित कर दिया कि तुष्टिकरण की राजनीति का अंत हो चुका। यहां

लोग कह रहे हैं, अब जात-पात नहीं, हिंदू एकाता ही सौभाग्य। अखिलेश अगर नहीं चेंते, तो सपा का सफर सबसे बाजूदर मुस्लिम तुष्टिकरण छोड़ना होगा, वरना हिंदू एकाता सबको नेस्टानाबूट कर देगी। इस सबके बीच यह हकीकत है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हवा का रस बदल रहा है। पश्चिम बंगाल ने साबित कर दिया कि तुष्टिकरण की राजनीति का अंत हो चुका। यहां

तमिलनाडु 'विजय' के निहितार्थ

—अभिनय आकाश—

विजय के माधन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। उन्होंने अपना माधन दिया था कि मैं सुपरस्टार नहीं आयां पर का बेटा हूँ। मैं शायद नहीं रोजगार देना चाहता हूँ। हर ईसान जन्म से समान है। थिरुकुरल की लाइन पिरपुकम इल्ला उई कूरुम यानीसब बरबकर है। इस लाइन ने विजय को हर वर्ग से जोड़ दिया।

अक्टूबर 2021 तमिलनाडु में निकाय चुनाव होने वाले थे और खबर आती है कि एक सुपरस्टार का फैन क्लब चुनावी मैदान में पहली बार उतरगा। फैन क्लब का नाम विजय मकल यकम वीएमआई। वीएमआई नाम के इस फैन क्लब को साल 2009 में बनाया था एक्टर विजय ने। जिन्हें उनके चाहने वाले कहते हैं विजय थलापति। थलापति जिसका शाब्दिक अर्थ है समाजदर या सेनापति। यही विजय अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में एक बड़े पॉलिटिकल कमांडर बनकर उभरे हैं। विजय की टीवी वीके ने सीएम स्टालिन की डीएमके का खेल पूरी तरह से तमिलनाडु में बिगाड़ दिया है। रझाणों में तमिलनाडु की सत्ता से सीएम स्टालिन आउट होते हुए इन्हें वक्त नजर आ रहे हैं। एक्टर विजय बनेंगे तमिलनाडु के किंग यह अभी निश्चय बनती हुई इस समय नजर आ रही है। तो आइए 234 सीटों के जग में कैसे विजय की आंखों में बदलाव पूरा समीकरण यह जानते हैं। कैसे आखिर एक्टर विजय ने अपनी रिलियों में लोगों से ऐसा क्या कहा कि जनता ने उन्हें खुलकर वोट दिया। एक्टर विजय के वो सात अक्षरवाक्य बड़े कोन से हैं जिन्होंने तमिलनाडु चुनाव में करारा उनकी पार्टी टीवीके का दमदार डेबू। सिस्वर खीन से सियासी चौधार का एक्टर विजय का सफर आखिरकार कैसा है। थलापति विजय किन्ने कर्कोडे के मालिक है?

बता दें कि तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतनगणना जारी है और रझाणों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। टीवी पहली बार चुनाव लड़कर ही 80 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाती हुई इस वक्त नजर आ रही है। वहीं बता दें कि डीएमके और आईआईडीएम के जैसे दिग्गज पार्टी इस समय पीछे हट चुकीं नजर आ रही है। यानी मुद्दाला सिर्फ चुनाव नहीं सिस्टम बनाम नया चेंडर बन गया है इस वक्त तमिलनाडु में अब यूर सूल बदल है सिर्फ एक चेंडर ने जोसेफ विजय चंद्रशेखर



की कि फैंस के लिए विजय थलापति 60 से ज्यादा फिल्में सुपरस्टार इमेज और करोड़ों की फकी फॉलोइंग तमिल सिनेमा में उनकी फिल्म रिजलज मालव कोई त्यौहार है यह कम नहीं होता और अब नवी स्टारडम वोट में बदलता हुआ तमिलनाडु की नजर आ रहा थलापति विजय की कुल संपत्ति की बात करें तो लगभग जो डाटा है जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 400 से 450 करोड़ आंकी जाती है। फिल्म ब्रॉड एंडोर्समेंट और प्रॉमोटीव हर जगह उनकी पकड़ मजबूत है।

साल 2024 में बता दें कि विजय ने अपनी पार्टी को लॉन्च किया और उनकी पार्टी का नाम टीवी के दिया। लेकिन इसकी नींव उन्होंने पहले ही रख दी थी अपने फैन क्लब विजय मकल ड्रयमक के जरिए। सियासत, सोशल बूट और सीमा कनेक्शन यानी एंटी इनकी अथाक नही हुई। सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में भूगोल बना दिया। विजय के माधन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। उन्होंने अपना माधन दिया था कि मैं सुपरस्टार नहीं आयां के घर का बेटा हूँ। मैं शायद नहीं रोजगार देना चाहता हूँ। हर ईसान जन्म से समान है। थिरुकुरल की लाइन पिरपुकम इल्ला उई कूरुम यानीसब बरबकर है। इस लाइन ने विजय को हर वर्ग से जोड़ दिया।

27 अक्टूबर 2024 में विक्रम मंडी में उनकी पहली रैली होती है। लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। लाल और पीला धारियों वाले झंडों से पूरा मानसक रखा था। इन सबसे बीच कहीं सूप में धीनी रोटली लगाते हुए विजय सभा में दखिलवा होतें हैं। लोगों का जोश आगले दिन के देश भर के अखबारों में छपने वाला था। उस वक्त से विजय ने अपनी विचारधारा भी साफ कर दी

ममता का किला ढहा, भगवा लहर का उदय



—डॉ. प्रियंका सौरभ—

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ऐतिहासिक जीत ने न केवल ममता बनर्जी की तुष्टिकरण को समाप्त कर दिया, बल्कि पूरे भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य को हमेशा की लिए बदल दिया। रझाणों और अल्पमत परिणामों के अनुयाय, बीजेपी ने 294 सीटों वाली विधानसभा में 168 से अधिक सीटें हासिल कर सफेद बहुमत प्राप्त कर लिया, जबकि टीएमसी 100 सीटों के आसपास सिमट गयी। कांग्रेस और सीपीआई(एम) जैसे परंपरिक विपक्षी दल क्रमशः 2-3 और 1-2 सीटों तक सीमित रह गए। यह परिणाम 2021 के चुनाव से पूरी तरह उलट है, जब टीएमसी ने 213 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। बीजेपी का वोट शेयर 2016 के मात्र 10 से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनावों में 39% हो चुका था, और अब यह पूर्ण सत्ता में तब्दील हो गया।



इस जीत के पीछे बहुराज्यामी कारक कार्यरत थे। सबसे पहले, टीएमके-इन्कनेसेली लहर ने जोरदार तरीके से अपना प्रभाव दिखाया। ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, कर्जमाफी, घुसपैठ और राजनीतिक हिंसा के मुद्दों आरोप लगे थे। विशेष गहन पुरीणण ('ए) अभियान के तहत वोट लिफ्ट से 27 लाख कतिब टीएमसी नाम हटाए गए, जिसने बंगालदेशी घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र में ला खड़ा किया। शांशा समुदाय को सफेद बड़ वोट बैंक हेतु नगरपालिका संरक्षण कानून (E1) के अंतर्गत न्याय के बाद बीजेपी को पूर्ण सत्तन किया। इसके अलावा, कानून-व्यवस्था की विपत्तियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जघ्द कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए, ने गैर-टीएमसी मतदाताओं को एकजुट किया। पहले चरण में 92.88 का रिफॉर्ड मतदान इस्ती असंतोष का प्रमाण था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ऐतिहासिक जीत ने न केवल ममता बनर्जी की तुष्टिकरण को समाप्त कर दिया, बल्कि पूरे भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य को हमेशा की लिए बदल दिया। रझाणों और अल्पमत परिणामों के अनुयाय, बीजेपी ने 294 सीटों वाली विधानसभा में 168 से अधिक सीटें हासिल कर सफेद बहुमत प्राप्त कर लिया, जबकि टीएमसी 100 सीटों के आसपास सिमट गयी। कांग्रेस और सीपीआई(एम) जैसे परंपरिक विपक्षी दल क्रमशः 2-3 और 1-2 सीटों तक सीमित रह गए। यह परिणाम 2021 के चुनाव से पूरी तरह उलट है, जब टीएमसी ने 213 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। बीजेपी का वोट शेयर 2016 के मात्र 10 से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनावों में 39% हो चुका था, और अब यह पूर्ण सत्ता में तब्दील हो गया।

इस जीत के पीछे बहुराज्यामी कारक कार्यरत थे। सबसे पहले, टीएमके-इन्कनेसेली लहर ने जोरदार तरीके से अपना प्रभाव दिखाया। ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, कर्जमाफी, घुसपैठ और राजनीतिक हिंसा के मुद्दों आरोप लगे थे। विशेष गहन पुरीणण ('ए) अभियान के तहत वोट लिफ्ट से 27 लाख कतिब टीएमसी नाम हटाए गए, जिसने बंगालदेशी घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र में ला खड़ा किया। शांशा समुदाय को सफेद बड़ वोट बैंक हेतु नगरपालिका संरक्षण कानून (E1) के अंतर्गत न्याय के बाद बीजेपी को पूर्ण सत्तन किया। इसके अलावा, कानून-व्यवस्था की विपत्तियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जघ्द कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए, ने गैर-टीएमसी मतदाताओं को एकजुट किया। पहले चरण में 92.88 का रिफॉर्ड मतदान इस्ती असंतोष का प्रमाण था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह

